दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 29 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 04

महत्वपूर्ण एवं खास

असम के 3 लापता स्कूली छात्रों के शव बरामद, 1 का सुराग नहीं

गुवाहाटी(आरएनएस)। असम के गुवाहाटी में पांडु घाट के पास ब्रह्मपुत्र से कक्षा 10 के लापता चार छात्रों के तीन शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे का सोमवार शाम तक कोई पता नहीं चल पाया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि चौथे छात्र अविनाश दास का पता लगाने के लिए बचाव अभियान सोमवार शाम तक जारी रहा, बावजूद इसके प्रतिकूल स्थिति के कारण बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान में रविवार को दीप सरकार, दयाल शेख और जीत दास के शव मिले। पीड़ित परिवारों के अनुसार, चारों अपनी निजी ट्यूशन कक्षाओं के बाद तैरने के बाद पांडु घाट के पास से लापता हो गए थे। उनके लापता होने का पता तब चला, जब स्थानीय लोगों को उनके स्कूल बैग, मोबाइल फोन और छात्रों की चप्पलें नदी के किनारे मिलीं।

अखनूर में बीएसएफ ने हथियार, गोला-बारूद और जाली नोट किए बरामद

जम्मू (आरएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते अखनूर इलाके में भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, नशीला पदार्थ और नकली नोट बरामद करने में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। बीएसएफ ने कहा कि एक विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, अखनूर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान मोटी सरकंडा घास में छिपा एक थैला मिला। यहां से चार पिस्तौल, आठ मैगजीन, 7.63 गुणा 25 एमएम की 190 गोलियां, एक किलो वजनी नशीला पदार्थ (संभावित हेरोइन) और 2,75,000 रुपये के नकली नोट मिले हैं। बयान के अनुसार, यह खेप क्षेत्र के राष्ट्र विरोधी तत्वों (एएनई) तक पहुंचाए जाने की संभावना थी, लेकिन बीएसएफ ने खेप को जब्त करके उनके नापाक प्रयासों को विफल कर दिया।

एनएमडीसी तथा सीएसआईआर ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए की साझेदारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केन्द्र तथा केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-आईएमएमटी ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देब और सीएसआईआर-आईएमएमटी के निदेशक डॉ. एस. बसु की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एनएमडीसी और सीएसआईआर-आईएमएमटी के बीच सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय खनिज उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यह संयुक्त उद्यम सीएसआईआर-आईएमएमटी और एनएमडीसी आरएंडडी केंद्र के व्यापक ज्ञान तथा अनुभव का इस्तेमाल निम्न ग्रेड लौह अयस्क प्रसंस्करण, कोयले का लाभ प्राप्त करने, खदानों के कचरे के उपयोग, तरल परिवहन और टंगस्टन प्राप्त करने के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए करेगा। एनएमडीसी के महाप्रबंधक (आर एंड डी) एस.के. चौरसिया और सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर के मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख एसपीबीडी डॉ. अशोक साहू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देब ने कहा, भारतीय खनन क्षेत्र जहां आत्मनिर्भरता के युग में प्रवेश कर रहा है, वहीं एनएमडीसी खनन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है। सीएसआईआर-आईएमएमटी के साथ यह सहयोग उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को की समर्पित

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित कीं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, रायपुर का नवनिर्मित परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किये। उन्होंने उन किसानों के साथ बातचीत की, जो नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करते हैं तथा सभा को भी संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के गांदरबल की मती जैतून बेगम से उनके द्वारा उपयोग की जा रही नयी कृषि पद्धतियों को सीखने की यात्रा, उनके द्वारा दूसरे किसानों को दिया गया प्रशिक्षण और घाटी में बालिका-शिक्षा के लिए काम करने के प्रति उनके समर्पण के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों में भी जम्मू-कश्मीर की लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी जोत वाले किसानों की जरूरतें सरकार की प्राथमिकता में हैं और उन्हें सभी लाभ, सीधे प्राप्त होते हैं।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक किसान और बीज उत्पादक कुलवंत सिंह के साथ बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने पूछा कि वह कैसे विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन करते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि पूसा के कृषि संस्थान में वैज्ञानिकों के साथ बातचीत से उन्हें क्या फायदा हुआ और ऐसे संस्थानों के साथ संपर्क में रहने को लेकर किसानों में क्या रुझान है। प्रधानमंत्री ने अपनी फसलों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करने के लिए किसान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बाजार तक पहुंच, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी कई पहल के माध्यम से किसानों को अच्छी कीमत दिलाने के लिए प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने बारदेज, गोवा की रहने वाली मती दर्शना पेडनेकर से पूछा कि वह किस प्रकार विविध फसलों की खेती और विभिन्न पशुओं का पालन-पोषण कर रही हैं। उन्होंने मती दर्शना से उनके द्वारा नारियल के फसल में किए गए मूल्यवर्धन के बारे में पूछा। उन्होंने इस बात को लेकर खुशी व्यक्त की कि कैसे एक महिला किसान एक उद्यमी के रूप में नई ऊंचाइंया हासिल कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने मणिपुर के थोइबा सिंह के साथ बातचीत करते हुए, सशस्त्र बलों में सेवा देने के बाद खेती का काम संभालने के लिए उनकी सराहना की। थोइबा की विविध गतिविधियों जैसे कृषि, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों ने प्रधानमंत्री को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान का उदाहरण बताते हुए उनकी प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के निवासी सुरेश राणा से पूछा कि उन्होंने मक्के की खेती कैसे शुरू की। प्रधानमंत्री ने कृषक उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए उत्तराखंड के किसानों की सराहना की और कहा कि जब किसान मिलकर काम करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले छह-सात वर्षों में कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान अधिक पौष्टिक बीजों पर है, जो खासकर बदलते मौसम में, नई परिस्थितियों के अनुकूल हैं।

प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के बीच पिछले साल विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर हुए टिड्डियों के हमले को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस हमले से निपटने के लिए काफी प्रयास किए और किसानों को बहुत अधिक नुकसान होने से बचाया।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब भी किसानों और कृषि को सुरक्षा कवच मिलता है तो उनका विकास तेजी से होता है। उन्होंने बताया कि भूमि के संरक्षण के लिए 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की किसान-हितैषी पहलों के बारे में बताया, जैसे - किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 100 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभियान, फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को नई किस्मों के बीज उपलब्ध कराना और इस प्रकार अधिक उपज प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ाने के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया गया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है और किसानों को 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। महामारी के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या को तीन गुना से अधिक बढ़ाया गया।

उरी में पकड़ा गया घुसपैठ की कोशिश कर रहा पाकिस्तानी आतंकी, दूसरा ढेर

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। उड़ी सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले रविवार को उड़ी सेक्टर के गोहलन इलाके में संदिग्ध हरकत देखने के बाद सतर्क जवानों ने पाया कि आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इस पर उन्होंने ललकारा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया।

कुछ दिन पहले भी हथलंगा जंगल क्षेत्र में तीन आतंकियों को मार गिराया गया था जो घुसपैठ कर दाखिल हुए थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। वहीं 18 सितंबर को भी उड़ी सेक्टर में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की एक कोशिश की गई थी जिसे सतर्क जवानों ने नाकाम बनाया था।

उड़ी सेक्टर में आतंकी घुसपैठ को लेकर सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल डी पी पांडेय ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सेना इस तरह की साजिशों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

7 से 11 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के परीक्षण की सीरम इंस्टीट्यूट को मिली अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के नियामक ने सीरम इंस्टिट्यूट को कोविड-19 के खिलाफ टीके के 7-11 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति दे दी है। सीरम पहले से 12-17 साल के बच्चों पर एक टीके का प्रयोग कर रहा है। 7-11 साल तक के बच्चों के लिए सीरम अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के टीके का परीक्षण कर रही है। सीरम इस टीके को भारत में कोवावैक्स के नाम से बना रही है। भारत में करीब डेढ़ साल से बंद स्कूलों को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है और बच्चों को भी टीका लगाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों के लिए टीके के इस ट्रायल के बारे में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के विशेषज्ञों की एक समिति ने कहा, विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने 7 से 11 साल तक के बच्चों को प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रायल के लिए भर्ती करने की अनुमति देने की अनुशंसा की बच्चों के टीकाकरण का इंतजार सीरम पहले से कोवोवैक्स का 12-17 साल के बच्चों पर परीक्षण कर रही है और शुरुआती 100 सहभागियों के लिए सुरक्षात्मकता का डाटा भी पेश किया है। इस टीके को भारत सरकार की स्वास्थ्य एजेंसियों ने अभी स्वीकृति नहीं दी है।

देश की लगभग 1।4 अरब आबादी में करीब 87 करोड़ वयस्कों को कम से कम पहली खुराक दी जा चुकी है। कुछ दिनों पहले सीरम इंस्टिट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने कहा था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोवोवैक्स को 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अगले साल जनवरी या फरवरी तक अनुमति मिल जाएगी। अभी तक भारत में 12 साल से बड़े बच्चों को देने के लिए सिर्फ जाइडस कैडिला की डीएनए कोविड-19 वैक्सीन को आपात स्वीकृति दी गई है। भारत में सुधरते हालात नोवोवैक्स ने मध्य और कम आय वाले देशों में कोवोवैक्स के उत्पादन के लिए पिछले साल सीरम के साथ लाइसेंस समझौते की घोषणा की थी। सीरम ने कोवोवैक्स के ट्रायल के लिए 10 भारतीय संस्थानों को चुना है।

महन्त मौत: हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की ज्यूडिशियल मानीटरिंग करने की याचिका दाखिल

प्रयागराज (आरएनएस)। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हो रही सीबीआई जांच की ज्यूडिशियल मानीटरिंग किये जाने की मांग को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र पिटीशन दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट की महिला वकील और सोशल एक्टिविस्ट सहर नकवी की तरफ से दाखिल लेटर पिटीशन यानी पत्र याचिका में तमाम दलीलें पेश करते हुए सीबीआई की जांच को हाईकोर्ट की निगरानी में ही कराए जाने की अपील की। लेटर पिटीशन को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ई-मेल के जरिये भेजा जा चुका है। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई किसी भी तरह की यह पहली अर्जी है।

हाईकोर्ट की महिला वकील सहर नकवी ने लेटर पिटीशन में कहा है कि महंत नरेंद्र गिरि और उनके मठ व अखाड़े के दुनिया भर में लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। लाखों लोगों की आस्था महंत नरेंद्र गिरि के साथ जुड़ी हुई थी। महंत नरेंद्र गिरि का शव जिस तरह संदिग्ध हालत में पाया गया था और पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर छेड़छाड़ हुई थी, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग इस मामले में आशंका जता रहे हैं।

देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कही जाने वाली जांच एजेंसी सीबीआई पर ज्यादातर लोगों को भरोसा तो है, लेकिन कुछ लोगों के मन में जांच को लेकर आशंका भी है। कुछ लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि सीबीआई किसी दबाव में आ सकती है या कुछ तथ्यों की अनदेखी कर जल्दबाजी व लापरवाही में जांच कर सकती है। ऐसे में सच सामने आ पाना और महंत की मौत के गुनहगार का राजफाश होने में मुश्किल हो सकती है।

वकील सहर नकवी ने अपनी पत्र याचिका में दलील दी है कि देश की जनता अदालतों पर सिर्फ भरोसा ही नहीं करती, बल्कि न्याय के मंदिरों से उसकी आस्था भी जुड़ी है। सीबीआई जांच का नतीजा जो भी आएगा, उस पर कुछ लोग यकीन नहीं कर पाएंगे और उस पर सवाल खड़े करेंगे। ऐसे में हाईकोर्ट अगर अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच कराएगा तो और समय-समय पर उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगकर जरूरी दिशा-निर्देश देता रहेगा तो जांच रिपोर्ट पर उंगली नहीं उठाएगा। लेटर पिटीशन में यह भी कहा गया कि महंत नरेंद्र गिरि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके साथ आम जनमानस की भावनाएं भी जुड़ी हुई थीं। ऐसे में सीबीआई जांच की ज्यूडिशियल मानीटरिंग बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट अगर इस मामले की जांच अपनी निगरानी में कराएगा तो वह ज्यादा पारदर्शी, वैज्ञानिक और विश्वसनीय तरीके से होगी।

महाराष्ट्र के यवतमाल में नदी में बही बस, चार की मौत

यवतमाल (आरएनएस)। महाराष्ट्र के यवतमाल के उमरखेड़ में मंगलवार सुबह एक जलमग्न पुल को पार करते समय राज्य परिवहन की बस के बह जाने से चार लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) नांदेड़-नागपुर बस बाढ़ के पानी में जलमग्न पुल को पार कर रही थी।

बमुश्किल कुछ मीटर की दूरी पर ही बस पानी की तेज धाराओं में फंस गई, चालक ने नियंत्रण खो दिया और यात्रियों के साथ वाहन नदी में गिर गई।

देर दोपहर तक, बचाव दल बस चालक, कंडक्टर और दो यात्रियों के शवों को निकालने में कामयाब रहे।

चार अन्य यात्रियों ने बस की छत पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की और तीन को ग्रामीणों ने बचा लिया।

रोजगार गारंटी मंत्री संदीपनराव भुमरे, (जो यवतमाल के संरक्षक मंत्री हैं) ने खोज और बचाव कार्यों की निगरानी की।

गुलाब चक्रवात के दुष्परिणाम के रूप में जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते आज शाम तेज बहाव वाली नदी में फंसी बस को निकालने के लिए रस्सियों वाली एक क्रेन को नदी किनारे पर तैनात किया गया था।

सीसीआई ने सभी कपास उत्पादक राज्यों में 5,543 कपास प्लकर मशीनों का किया वितरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई)ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत सभी कपास उत्पादक राज्यों (आकांक्षी जिलों सहित) में 5,543 सीमांत और छोटे किसानों के बीच करीब चार करोड़ रुपये की कीमत की 5,543 कपास प्लकर मशीनें वितरित की हैं।

चूंकि सीसीआई, कपास के किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए कच्चे कपास की बाजार दर एमएसपी दरों से नीचे आने की स्थिति में कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के लिए कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक नोडल एजेंसी है, इसलिए, निगम का सीएसआर बजट बहुत सीमित रहता है। इस बाधा के बावजूद, निगम ने कपास उगाने वाले सभी राज्यों में सीमांत और छोटे किसानों को कपास प्लकर मशीनें वितरित कीं।

भारत में हाथों के द्वारा अधिकांश कपास पौधों से अलग किया जाता है, जिसके लिए ज्यादा श्रमबल की आवश्कता पड़ती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे दूसरे प्रमुख कपास उत्पादक देशों के विपरीत, भारत में कपास किसानों की छोटी भूमि जोत, बुवाई/कपास को पौधे से निकालने के पैटर्न (3-4 तुड़ाई) और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण बड़ी मशीनों द्वारा पूरी तरह से मशीनीकृत कटाई भारत में सफल नहीं हुई है। इसलिए, किसानों के लिए लागत को कम करने के लिए हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन (कपास को पौधे से अलग करने की मशीन) एक विकल्प है और मानव श्रम के साथ कपास को पौधे से अलग करने(मैनुअल पिकिंग) के कारण खेतों के स्तर पर संदूषण को रोकने का एक हल है।

हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन एक हल्के वजन (लगभग 600 ग्राम) की मशीन है जिसके अंदर रोलर्स की एक जोड़ी होती है जिसके बाहरी परिधि पर छोटे किनारों वाले दांत होते हैं और यह हल्के वजन 12 वोल्ट द्वारा संचालित होता है। कपास रोलर्स में उलझ जाता है और सीधे उससे जुड़े कलेक्शन बैग में इकट्ठा हो जाता है। मशीन का डिजाइन उसे क्षेत्र में काम करने के लिहाज से आसान बनाता है और यह 8,000 रुपये (लगभग) प्रति मशीन की कम कीमत के साथ किफायती भी है।

कपास प्लकर मशीनों के लाभ इस प्रकार हैं,- कपास किसानों के लिए मैनुअल पिकिंग में स्वास्थ्य खतरों के जोखिम को कम करना (यानी कीड़े के काटने का जोखिम, लंबे समय तक खड़े रहने के कारण पीठ दर्द, पैरों और हाथों में चोट लगना/काटना आदि)।

कपास की कटाई के कौशल में सुधार, दुर्लभ और महंगे श्रम पर निर्भरता कम करना तथा कपास किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।

खेतों के स्तर पर संदूषण को कम करके कपास की गुणवत्ता में सुधार करना।

कटाई की लागत में कमी (श्रम की कम आवश्यकता), कम कचरा एवं संदूषण और बेहतर गुणवत्ता वाले कपास की बिक्री पर प्रीमियम के साथ कपास किसानों का वित्तीय लाभ बढ़ सकता है।

अच्छी गुणवत्ता वाले स्वदेशी कपास की उपलब्धता के कारण सूती धागे, वस्त्र और मूल्य वर्धित उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सकती है।

कपास की हाथों से कटाई में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए और खेतों के स्तर पर संदूषण में कमी करके कपास की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सीसीआई ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत कपास प्लकर मशीन का वितरण शुरू किया है।